

विचार

नगर निगम में भ्रष्टाचार और बिल्डरों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

इस देश के किसी भी शहर के किसी भी नगर निगम या विकास प्राधिकरण के कार्यालय चले जाइए, बाहर घूमते दलालों की फौज यह बताते हुए नजर आती है कि वहां किस पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के तमाम दावों के बावजूद आम लोगों का रिश्वत दिए बिना कोई काम हो पाना, आज भी उतना ही मुश्किल है जितना कई वर्षों या दशकों पहले हुआ करता था। हालत यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना निजी रिहायशी मकान बनवाने के लिए जैसे ही घर के सामने रेत, रोड़ी, बदरपुर और ईट मंगवाते हैं वैसे ही पुलिस और नगर निगम अथवा विकास प्राधिकरण का कोई न कोई बंदा रिश्वत की मांग को लेकर पहुंच जाता है। लेकिन इन्हीं के इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होते रहते हैं, बिल्डरों की मनमानी चलती रहती है और ये चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जैसे जिलों में तो हालात कहीं ज्यादा भयावह और बेकाबू हो चुके हैं। शहरीकरण की अंधी दौड़ में भ्रष्टाचार और बिल्डरों की मनमानी के कारण आम लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली की हालत भी इस मामले में बेहतर नहीं है। दिल्ली नगर निगम के कामकाज के बारे में तो सब जानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम पर जिस तरह की तल्ख टिप्पणी कर दी है, उससे एक बार फिर से एमसीडी की कड़वी सच्चाई बाहर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली नगर निगम की निष्क्रियता पर गंभीर टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि क्या दिल्ली नगर निगम बिल्डरों के हाथ में चल रहा है ? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बैंच के सामने सोमवार को एक मामले में दिल्ली नगर निगम ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण को हटा दिया गया था और इसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के रवैये पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि, कोई पीआईएल दायर करता है, तब जाकर आप जागते हैं और दिखावे की कार्रवाई करने लगते हैं। हाई कोर्ट भी आपकी बातों को मानकर मामले को बंद कर देता है। क्या नगर निगम बिल्डरों के हाथ में चल रहा है ? सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई से जांच करवाने की बात कहते हुए दिल्ली नगर निगम को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसमें यह पूछा गया कि मामले की गहन जांच क्यों न कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केवल मौके का मुआयना ही काफी नहीं है, बल्कि दिल्ली नगर निगम की कार्यप्रणाली की भी जांच होनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि अवैध निर्माण की अनुमति किन कारणों से दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने याँचिकाकर्ताओं को आर्किटेक्ट एवं इंजीनियर जैसे स्वतंत्र विशेषज्ञों के नाम सुझाने को भी कहा है, जो साइट का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दे सके।

नेताओं-नौकरशाहों

योगेंद्र योगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को खुली छूट दे दी है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है और वह देश को इस बुराई से मुक्त करने के लिए पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दृढ़निश्चय के बावजूद भारत में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार हो या राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें, सभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बढ़े दावे-वादे करती रही हैं, किन्तु यह समस्या सुरक्षा के मुंह की तरह विकराल होती जा रही है। करप्तान परसेप्शन इंडेक्स-2024 की भ्रष्टाचार की सूची वाले देशों में भारत 96वें पायदान पर पहुंच गया है। साल 2023 में भारत की रैंक 93 थी।

का सार्वजनिक क्षेत्र स्कोर 13 विभिन्न से प्राप्त कम से कम ये सोर्स विश्व बैंक विभिन्न प्रतिष्ठित संसीपीआई की गणना रूप से समीक्षा किया जा सके विधासंघ भव मजबूत में विदेशी निवेश प्रमुख कारण भ्रष्टाचार की अंतर्राष्ट्रीय साधायहां निवेश करने से और लघु व मध्यम नहीं सके हैं। भारत की दिशा में अग्रसर की जंजीर इसके ब

भारत इस सूची में पड़ोसी देशों की ज्यादा बुरी हालत पर कुछ राहत महसूस कर सकता है। भ्रष्टाचार की इस सूची में भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 135 नंबर पर और श्रीलंका 121 पर हैं, जबकि बांग्लादेश की रैंकिंग और भी नीचे 149 पर चली गई है। इस लिस्ट में चीन 76वें स्थान पर है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट राष्ट होने की सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद फिनलैण्ड और सिंगापुर हैं। 1995 से 2024 तक भारत में भ्रष्टाचार की औसत दर 78.03 रही, जो 2024 में 96.00 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और 1995 में 35.00 के रिकॉर्ड रिपोर्ट तक आया था।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी सीपीआई दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वैश्विक भ्रष्टाचार रैंकिंग है। यह मापता है कि विशेषज्ञों और व्यवसायियों के अनुसार प्रत्येक देश

दिल्ली की नई मुख्यमंत्रीः चुनौतियों का सफर

डॉ राकेश कुमार आर्य

प्रधानमंत्री मोदी अपनी अलग कार्य शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुयमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के अपने निर्णय को भी अंतिम क्षणों तक गोपनीय रखा। मीडिया के लोग कई लोगों के नामों को लेकर अनुमान लगाते रहे, परंतु हर बार की भाँति इस बार भी प्रधानमंत्री ने अपने निर्णय की गोपनीयता को अंतिम क्षणों तक रहस्यमय बनाए रखा और हमने देखा कि दिल्ली की शालीमार गार्डन सीट से पहली बार विधायक बनकर आई रेखा गुप्ता को उन्होंने दिल्ली का मुयमंत्री बनवा दिया। निश्चित रूप से रेखा गुप्ता के इस चयन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु स्पष्ट रूप से पार्टी और देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, इसलिए यही कहा जाएगा कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ एक अच्छा समन्वय स्थापित करते हुए रेखा गुप्ता को यह दायित्व दिया। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई प्रदेशों में ऐसे वेहरों को आगे ला चुके हैं, उनका वह परीक्षण सफल ही रहा है।



इसके पीछे चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या प्रधानमंत्री मोदी या उनके अन्य वरिष्ठ परामर्शदाता हों, सभी का उद्देश्य एक ही रहता है कि नया %बेदाग चेहरा% लोगों को रास आएगा और वह मिले हुए अवसर के दृष्टिगत अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा। जब %दागदार चेहरों% को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो वे उन्हें पूर्ण निष्ठा के साथ निभा नहीं पाते हैं या फिर अपनी परंपरागत कार्य शैली का परिचय देते हुए भ्रष्टाचार जैसे कार्यों में लग जाते हैं। जिसकी क्षति पार्टी को उठानी पड़ती है और अंत में राष्ट्र को भी ऐसे चेहरों से हानि ही मिलती है। इस प्रकार के नए बेदाग चेहरों को आगे लाने से पार्टी और देश दोनों को दूर तक और देर

की पाइपलाइन कई स्थानों पर गल गई है। जिससे लोगों को मलमूत्र मिले पानी को पीने के लिए अभिशास होना पड़ गय है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें लोगों को दूध मिलना संभव है परंतु सही पानी मिलना उनके लिए कठिन हो गया है। बिजली के खंभों या लाइन की व्यवस्था भी कई क्षेत्रों में बहुत खराब हो चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात को लेकर भी यही कहा जा सकता है। ऐसे में पानी और बिजली की नई लाइन बिछाना और लोगों के स्वास्थ्य व सुविधा के दृष्टिगत उन्हें स्वच्छ पानी और बिजली उपलब्ध कराना दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।

यहि बहु ऐसा कहती हैं तो नौटंकी बाज के जगहाल के

का आग लान से पाठा आ दश दाना का दूर तक आर दर तक लाभ मिलना स्वाभाविक है। बस अपनी इसी दूरगमी सोच के चलते भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्तमान नेतृत्व ऐसे चेरहों को सामने लाता रहता है। पार्टी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर नारी सशक्तिकरण के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया है। वैसे भी इस समय देश में केवल एक ही महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का नेतृत्व कर रही हैं। जब बार-बार नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही हो, तब भाजपा ने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर इस चर्चा को मानो एक नई ऊँचाई दी है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जिस प्रकार के जरीवाल ने पिछले 11 वर्ष में %रेवड़ी बाटनें% की परंपरा के आधार पर शासन किया है, उसके चलते बहुत से विकास कार्य प्रभावित हए हैं। दिल्ली के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें पानी

गंभीर नेतृत्व को आगे लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए अनिवार्य था। रेखा गुसा के भीतर ऐसे ही एक गंभीर व्यक्तित्व को देखा गया है, जो प्रत्येक प्रकार की नौटंकी का समना करते हुए धैर्य के साथ दिल्ली की जनता की सेवा कर सके।

स्पष्ट है कि भाजपा न सत्ता का स्वाद लेने के लिए रखा गुसा को मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं दिया है, बल्कि पार्टी को निरंतर सत्ता में बनाए रखकर राष्ट्र सेवा करते रहने के लिए उन्हें यह दायित्व दिया गया है। भाजपा की इस प्रकार की रणनीति को केजरीवाल और राहुल गांधी भली प्रकार जानते हैं। भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री के चेहरे को ढूँढ़ने में लगे 10-12 दिन के समय को लेकर इन दोनों पार्टियों को इसी बात की चिंता हो रही थी कि भाजपा उन्हें देर तक सत्ता से दूर रखने के लिए मुख्यमंत्री बनाने में जिस प्रकार विलंब कर रही है, वह उनके लिए ही हानिकारक होगा।

इस बार के विधानसभा चुनाव में यमुना को सफाई का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया गया। हमारा मानना है कि यमुना की सफाई को एक मुद्दा बनाया भी जाना चाहिए था। जिस प्रकार दिल्ली के अनेक गंदे नाले इस नदी को मृत नदी के रूप में परिवर्तित करते जा रहे हैं, वह न केवल दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को विशेष परिश्रम करना होगा। हमारा मानना है कि दिल्ली के गंदे नालों के पानी को सीमेंट या लोहे के बड़े-बड़े पाइपों के भीतर डालकर नदी के भीतर इन पाइपों की एक समानांतर लाइन बिछाकर उस पानी को हरियाणा या उत्तर प्रदेश की ओर दूर ले जाया जाए। वहां उसे पीने योग्य या कृषि भूमि को सीधे योग्य बनाकर दोबारा ठीक किया जाए। इसके लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों की एक संयुक्त टीम गठित की जाए अथवा एक प्राधिकरण बनाया जाए। इस प्रकार दिल्ली के गंदे नालों का एक बूँद पानी भी यमुना नदी में नहीं गिर पाएगा, जिससे नदी को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी।

**मातृभाषाएं संवारती हैं संस्कार और
संस्कृति को**

मातृभाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपराओं, जीवनमूल्यों और इतिहास को संजोने का एक सशक्त साधन है। यह समाज, संस्कृति एवं राष्ट्र के लिए पहचान का महत्वपूर्ण साधन होती है। शोध बताते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़कर अधिक अच्छी तरह से समझ विकसित करते हैं, वहीं आमजन के लिये संवाद एवं व्यवहार का प्रभावी माध्यम भी यही है। इससे उनकी बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। यूनेस्को ने मातृभाषा के महत्व को समझते हुए मातृभाषा के संरक्षण और बहुभाषी शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा 1999 में की और 2000 से इसकी शुरुआत की। इस वर्ष 25वें वर्षगांठ मनाते हुए इसकी थीम भाषा का महत्व- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह है, जो 2030 तक अधिक समावेशी और टिकाऊ विश्व के निर्माण के लिए भाषाई विविधता पर प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता को रेखांकित करेगा। भाषाई विविधता को बढ़ावा देने, लुप्तप्राय भाषाओं की रक्षा करने और बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को प्रदर्शित करने पर जोर दे रहा है। तकनीकी विकास और इंटरनेट के सुरक्षित विस्तार के साथ, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्थानीय और मातृभाषाओं को डिजिटल माध्यमों में कैसे संरक्षित किया जाए। यह दिवस हमें भाषाओं को डिजिटल रूप में संरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है। यूनेस्को का मानना है कि स्थायी समाज के लिए सांस्कृतिक और भाषाई विविधता बहुत जरूरी है। शांति के लिए अपने जनादेश के तहत यह संस्कृतियों और भाषाओं में अंतर को बनाए रखने के लिए काम करता है जो दूसरों के लिए सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज अपनी भाषाओं के माध्यम से अस्तित्व में रहते हैं जो पारंपरिक ज्ञान और संस्कृतियों को स्थायी तरीके से प्रसारित और संरक्षित करते हैं। भाषाई विविधता लगातार खतरे में पड़ती जा रही है क्योंकि अधिकाधिक भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं। वैश्विक स्तर पर 40 प्रतिशत आबादी को उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है जिसे वे बोलते या समझते हैं। फिर भी, बहुभाषी शिक्षा में प्रगति हो रही है, इसके महत्व की समझ बढ़ रही है, खासकर प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में, और सार्वजनिक जीवन में इसके विकास के लिए अधिक प्रतिबद्धता है।

नेताओं-नौकरशाहों की जिम्मेदारी के बगैर भ्रष्टाचार को मिटाना असंभव

का सार्वजनिक क्षेत्र कितना भ्रष्ट है। प्रत्येक देश का स्कोर 13 विभिन्न भ्रष्टाचार सर्वेक्षणों और आकलनों से प्राप्त कम से कम 3 डेटा स्रोतों लिया जाता है। ये सोर्स विश्व बैंक और विश्व अर्थिक मंच सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। सीपीआई की गणना करने की प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जारी की जाने वाली सूची यथासंभव मजबूत और सुसंगत है या नहीं। भारत में विदेशी निवेश अपेक्षाकृत नहीं आने का एक प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण भारत की अंतरराष्ट्रीय साख कमजोर है। विदेशी कंपनियां यहां निवेश करने से कठतरी हैं। देश के उद्योगपति और लघु व मध्यम व्यवसायी इसकी मार से बच नहीं सके हैं। भारत एक तरफ वैश्विक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर है, वहां दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की जंजीर इसके बढ़ते कदम को रोक रही है। ऐसा

देश का शायद ही कोई चुनाव होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया हो। मोदी ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार पर प्रहर करने में कसर बाकी नहीं रखी। संसद में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरे लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाइ चुनावी जीत या हार के पैमाने पर नहीं है। मैं चुनाव जीतने या हारने के लिए भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहा हूं। यह मेरा मिशन है, मेरा विश्वास है। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। मैं इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और आम लोगों के मन में भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए पूरे दिल से काम कर रहा हूं।

प्रधानमंत्री के देश से पूरी तरह भ्रष्टाचार के खात्मे के प्रति प्रतिज्ञा लेने के बाबजूद यदि यह



संक्रामक रोग की तरह बढ़ता ही जा रहा है तो
इसके लिए ज्यादातर राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं।
क्षेत्रीय दलों की हालत यह है कि उनका एकमात्र
मकसद किसी भी हालत में सत्ता में बने रहना है।
इसके लिए बेशक भ्रष्टाचार से किसी भी हट तक
समझौता क्यों न करना पड़े। यही वजह रही है कि
झंडिया गठबंधन लगातार चुनावों में शिकस्त खाता

रहा है। आश्वर्य यह है कि लोकसभा चुनावों और राज्यों के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बावजूद विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार को कभी भी प्रमुख चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। भ्रष्टाचार को लेकर हालत ये हैं कि जैसे ही कोई भी विपक्षी दल भ्रष्टाचार का जिक्र करता है, तत्काल सत्तारूढ़ दल न सिर्फ उसके बचाव में उत्तर आता है बल्कि विपक्षी दल के

A high-contrast, black-and-white image showing a dark silhouette of a hand and arm on the right side. The hand is positioned palm-up, with fingers slightly spread. In the center of the hand, there is a small, dark, rectangular object, possibly a coin or a piece of paper. On the far left edge of the frame, another dark, angular shape is visible, suggesting a second hand or a different perspective. The background is a solid, bright white.

कारनामे गिनाने लगता है। यही बजह है कि क्षेत्री दल अपने राज्यों में मनमानी करने पर आमदा है। यदि केंद्रीय जांच व्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को कार्रवाई करता है तो राज्य के सत्तारुढ़ दल इबदले की कार्रवाई करार देने लगते हैं। इसके उदाहरण पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और कर्नाटक के सिद्धरमैया की सरकार है। इतना ही नहीं राजनीतिक दलों का भरसक प्रयास होता है कि अदालतों चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को भी प्रभावित कि-

गौरतलब है कि सीनियर वकील हरीश सालम् सहित देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवार्ड चंद्रचूड़ा को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाया।

શિક્ષા મંત્રી કી તમિલનાડુ સીએમ કો ચિદ્રી

નई દિલ્હી (એજેસી)। ટ્રાઇલોનેજ વિવાદ પર કેંદ્રીય શિક્ષા મંત્રી ધર્મદેવ પ્રધાન ને શુક્રવાર કો તમિલનાડુ કે સીએમ એક સ્ટેટિન કો લેટર લિખ્યા. ઉહનેં રાચ્ય મેં હો રહે નેશનલ એજુકેશન પોલસી કે વિરોધ કી આલોચના કી. ઉહનેં લિખ્યા, કિસી ભી ભાષા કો થોણે કા સવાલ નહીં હૈ. લેકિન વિદ્યાર્થી ભાષાઓ પર અત્યધિક નિર્ભાત ખુદ કી ભાષા કો સર્વીસ કરતી હૈ. નई રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ એ હો ઠીક કરને કા કાયમ રહ્યી હૈ ઔર યદુઃખિત કરતી હૈ કિ સ્ટેટ્ઝેન્ડ અપણી પદ્દતિ કી ભાષા સાંખ્યા જારી રહે. ધર્મદેવ પ્રધાન ને અપણે લેટર મેં મઈ 2022 મેં ચેર્ચ મેં પીએમ માર્દી કે તમિલ ભાષા શાશ્વત હૈ કે બાયન કા જિક કરતે હુએ લિખ્યા- મોદી સરકાર તમિલ સંસ્કૃતિ ઔર ભાષા કો વૈશિષ્ટ સ્તર પર બઢાવા દેને ઔર લોકપ્રિય બનને કે લિએ પૂરી તરહ પ્રતિબદ્ધ હૈ. મેં આપીલ કરતા હું કિ શિક્ષા કા રજાનેતિકણ ન કરેં. દરાસલ, ધર્મદેવ પ્રધાન ને 15 ફરવરી કો વારાણસી કે એક કાર્યક્રમ મેં તમિલનાડુ કો રાજ્ય સરકાર પર રાજનીતિક હિંતોનો કા સાથે કા આરોપ લગાયા થા. 16 ફરવરી સ્ટેટિન બોલે- ધમકીની નહીં સહેંગે તમિલનાડુ સીએમ ને કહા થા કિ તમિલ લોગ બ્લૈકમેલિંગ યા ધમકી સહન નહીં કરીએ. અગ્ર રાચ્ય કો સમગ્ર શિક્ષા કો ફડ સે વિનિત કિયા ગયા, તો કંદું કો %તમિસ્સ યુનિયન નેચરાં યાની તમિલનો કે મજબૂત વિરોધ કા સામાન કરના પડેણા.

એકનાથ શિંડે કી કાર મેં બમ કી ધમકી, દો ગિરપતાર

મુર્વિં (એજેસી)। મહારાષ્ટ્ર કે ડિપ્ટી સીએમ એકનાથ શિંડે ને શુક્રવાર કો કહા, મુશ્કેલ્સે મેં મત લોજિએ, જિહોને મુશ્કેલ્સે હલ્કે મેં લિયા હૈ, ઉનસે મૈં પહેલે હી કહ ચુકા હું કી મેં સામાચ્ય પાર્ટી કાર્યકર્તા હું લેકિન મેં બાલા સાહેબ કા કાર્યકર્તા હું ઔર સભી કો મેરી ઇમ બાત કો સમજ્ઞ લેના ચાહિએ. શિંડે કા વહ બયાન ઉનકો જાન સે મધ્યમ કી ધમકી ન કરી આ યાં. 20 ફરવરી કો મેલ કે જારી રીતે કાર મેં બમ વિસ્કોટ કરને કી ધમકી દી ગઈ. મંત્રાલય ઔર જેઝ એસ્પેલસ ને ધમકીની કે ઇસ માલે મેં બુલદાળા સે દો લોગોનો કો ગિરપટાર કિયા હૈ. આરોપ્યાંને કે નામ માંશ અચ્યુતરાવ વાયલ (35) ઔર અભય ગાજાન શિંગણે (22) હૈનું. દોનોં બુલદાળાની કે ડેઝાલાં માહી ગાંબ કે રહ્યે વાલે હૈનું. 2022 મેં હલ્કે મેં લિયા થા, મેંસે સરકાર બદલ્યું હી તુંહોની કહા- જી ભારત કો

દિલ્હી મેં આતિથી-પૂર્વ મત્તીયો કે પરસનાલ સ્ટાફ હૃતાને ગા

નई દિલ્હી (એજેસી)। દિલ્હી મેં મુખ્યમંત્રી પદ કી શપથ લેને કે એક દિન બાદ રેખા ગુસા ને પૂર્વ સીએમ આતિથી અનુભૂતિ ને તમિલનાડુ કો હાથ નીચે લેને કે પરસનાલ સ્ટાફ કો હાથ નીચે લેને કે નિયુક્ત કિયા થા તુંહોની ફૌન અપણે મૂલ વિભાગ મેં રિપોર્ટ કરને કો કહા ગયા હૈ. મુખ્યમંત્રી રેખા ગુસા આજ દોપહર સચિવાલય પછુંચી ઔર મત્તીયોં-અફસરોને કે સાથ મીટિંગ કીયા.

પ્રધાનમંત્રી બોલે-લીડરશિપ પર વિવેકાનંદ કા મંત્ર લેકર આગે બઢના હૈ

નई દિલ્હી (એજેસી)। પ્રધાનમંત્રી નરેંદ્ર મોદી ને શુક્રવાર કો દિલ્હી કે ભારત મંડળમ મેં (સ્ક્રુલ ઑફ અન્ટ્રેપેટ લીડરશિપ) કાર્બલ્સેવ કે પહેલે એઢિશન કા ઇન્ઝિનિયરિંગ કા ઇન્સ્ટિન્યુટ ને કહા- કિસી ભી દેશ કે નિર્માણ કે લિએ વહાની કે વ્યક્તિ યાની જરૂરી હૈ. એન્ફાએમ ને કહા- કિસી ભી ઊંચાઈ કો પ્રાપ્ત કરતી હૈ. એન્ફાએમ ને કહા- કિસી ભી ઊંચાઈ કો પ્રાપ્ત કરતી હૈ. તો આંખ જન સે હી શુશ્રૂ હોતી હૈ. હું ક્રેટર મેં વેહતરિન લીડર્સ કા વિકાસ બચુત જરૂરી હૈ. વહ સમય કી માંગ હૈ. ઇસાલે એસ્પોર્ટ ભારત કો વિકાસ યાત્રા મેં એક બહુત મહત્વર્ણ (એન્ડ્રોડ) કદમ હૈ. ઉહનેં કહા- સ્વામી નેતૃત્વ ની જરૂરત પીએમ ને

ગુલામી સે બાહર નિકાલકર બદલાવ લાના ચાહેતે થે. ઉનકા વિશ્વાસ થા કી અપાર 100 લીડર ઉનકે પાસ હોય, તો વહ ભારત કો આજાદી હી નહીં, બલ્કિ દુનિયા કા નંબર વન દેશ બના સકતે હૈનું. ઇસી મંત્ર કો લેકર હમ સવબો આગે બઢના હૈ.



કહા- આજ હર ભારતીય 21વીં સદી કે વિકસિત ભારત કે

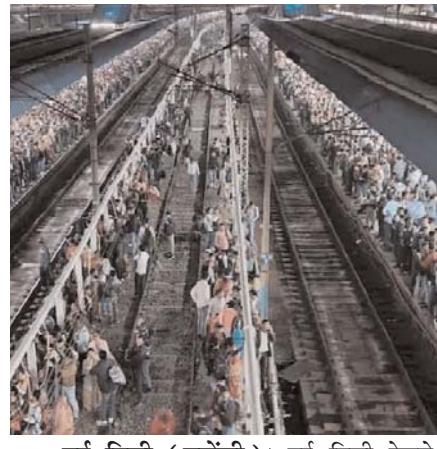
લિએ દિન-રાત કામ કર રહા હૈ. એસે 140 કરોડ દેશ મેં

સેક્ટર મેં, હર કાર્યક્ષેત્ર મેં, જીવન કે હર આધાર મેં હે

ઉત્તમ સે ઉત્તમ નેતૃત્વ કી આવશ્યકતા હૈ. કુછ આયોજન એસે હોતે હૈ, તો હુદય કે બનું કરીબ હોતે હૈ અને આજ કા યે સ્થુર પ્રોગ્રામ ભી એસા હી હૈ.

2. નવાચાર બદાને વાલે સંસાધનોની આવશ્યકતા ઉંહોને કહા- કિસી ભી દેશ કો પ્રગતિ કરતે કે લિએ ન કેબલ પ્રાકૃતિક સંસાધનોની આવશ્યકતા હોતી હૈ, બલ્કિ માનવ સંસાધનોની આવશ્યકતા હોતી હૈ. 21વીં સદી મેં હેસે સંસાધનોની આવશ્યકતા હોતી હૈ. જો નવાચાર કો બઢાવા દે સકે ઔર કૌશલ કો પ્રભાવી ઢાંચે સે ચૈલ કર સકેં. હેસે વૈજ્ઞાનિક રૂપ સે નેતૃત્વ વિકાસ મેં તેજી લાની ચાહીએ।

નई દિલ્હી સ્ટેશન પર ભગડ્ડ કે વીડિયો હૃતાને કે નિર્દેશ



નई દિલ્હી (એજેસી)। નેતૃત્વ રેલવે સ્ટેશન પર 15 ફરવરી કો હુંદું ભગડ્ડ મેં 18 લોગોની મીં મોટ હો ગઈ થી. માલાલે મેં અબ તક જાંચ રિપોર્ટ નહીં આઈ હૈ, લેકિન રેલવે ને એક ફરમાન જરૂર જારી કિયા હૈ. હિંદુસ્તાન ટાઇસ્પ

કી રિપોર્ટ કે અનુસાર રેલ મંત્રાલય ને સોશલ મીડિયા પ્લોટફોર્મ જી કો નોટિસ જારી કર 288 વીડિયોઝ લિંક હૃતાને કે નિર્દેશ દિયા હૈ. મંત્રાલય ને 17 ફરવરી કો યદ નોટિસ બેજા થા ઔર એક્સપ્સ કો 36 ઘટે મેં બટાના સે જુડે સભી વીડિયો લિંક હૃતાને કા નિર્દેશ દિયા થા. મંત્રાલય કે નોટિસ મેં કહા ગયા કી યદ નૈતિકતા કે સાથ જી કે કાંટેંટ પોલસી કે ભી ખિલાફ હૈ. ઇસ તરહ કે વીડિયો સોશલ મીડિયા પર શેરાને સે કાનૂન-વ્યવસ્થા કી સિદ્ધિત ખરાબ હો સકતી હૈ. અભી ટ્રેનોની મેં ભારી ભીડ હૈ, ઇસે દેખતે હું રેલવે કા આંપરેશન પીંડાં કે પ્રમાણિત હો સકતી હૈ. દિસ્પર મેં વીડિયો હરતોને કા અધિકતા એક પ્રાણી શિલ્પિની હુંપું હૈ. દિસ્પર કે ટોકટોની મેં બેન્ટો સે જાંચ કરતી હૈ. દિસ્પર કે ટોકટોની મેં બેન્ટો સે જાંચ કરતી હૈ. દિસ્પર કે ટોકટોની મેં બેન્ટો સે જાંચ કરતી હૈ. દિસ્પર કે ટોકટોની મેં બેન્ટો સે જાંચ કરતી હૈ. દિસ્પર કે ટોક

